

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक २४ मार्च, 2014

विषय:- मैं फलेम आयरन एण्ड स्टील्स प्राइलि मुजफ्फरनगर (उ०प्र०) को औद्योगिक प्रयोजन (इंगट एवं ब्लेट्स के उत्पादन) हेतु ग्राम मुन्डलाना, तहसील रुड़की, जनपद हरिद्वार में कुल 0.4869 हैं भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-376/जिला भूमि व्यव-2013-14 दिनांक-09.09.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मैं फलेम आयरन एण्ड स्टील्स प्राइलि मुजफ्फरनगर (उ०प्र०) को औद्योगिक प्रयोजन (इंगट एवं ब्लेट्स के उत्पादन) हेतु ग्राम मुन्डलाना, तहसील रुड़की, जनपद हरिद्वार में कुल 0.4869 हैं भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जर्मिंदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति/सहमति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कंलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2- केता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (इंगट एवं ब्लेट्स के उत्पादन) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होगा।

3— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकरणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5— शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6— इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग केवल इंगट एवं ब्लेट्स का उत्पादन कार्य हेतु ही किया जायेगा।

7— जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।

8— इकाई राज्य सरकार/शासन से सम्बन्धित विभाग से प्रस्तावित औद्योगिक उत्पाद के विनिर्माण हेतु सभी आवश्यक अनुज्ञाएं/स्वीकृतियां स्वयं प्राप्त कर उद्योग की स्थापना करेगी।

9— अनुमति उपरान्त धारा-143 के अन्तर्गत कृषिक भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु परिवर्तित करायेगी।

10— इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग उद्योग स्थापना/विस्तार के लिए ही किया जायेगा।

11— भूमि क्रय करने के उपरान्त निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये निर्माण का प्लान सीड़ा/विनियमित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

12— इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

13— आवेदक द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्यम में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

14— इकाई को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

15— प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा।

16— इकाई को निर्माण से पूर्व यूपी०सी०एल० (ऊर्जा विभाग) से भी अनापत्ति प्राप्त करनी होगी ।

17— सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे ।

18— किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्य के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय ।

19— भूमि का विक्य अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्य किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

20— योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी ।

21— उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी ।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से भी समस्य शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव ।

पृ०प०सं०— 75 / समदिनांकित / 2014

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- 2— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 3— आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी ।
- 4— निदेशक, मै० फलेम आयरन एण्ड स्टील्स प्रा०लि०, 786 / न्यू राणा हाउस मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०) ।
- 5— निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
- 6— प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
- 7— गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
20/
(संतोष बडोनी)
उप सचिव ।